" " प्रदूषण नियंत्रण के लिए राज्यों की सहायता"

2210.**श्री रामजी लालः** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार प्रदूषण रोकने के लिए राज्यों को प्रत्येक वर्ष कितनी सहायता देती है, और

(ख) 1991 से राज्यों में प्रदूषण रोकने के संबंध में अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री काली नाथ): (क) प्रदूषण नियंत्रण के लिए विभित्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोडों , प्रदूषण नियंत्रण समितियों राज्यों सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रतिवर्ष प्रदान की जाने वाली सहायता 30 करोड़ रूपए से अधिक है।

(ख) देश में प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैंः

(I) औद्योगिकी वाणिज्यिक और शहरों के आवासीय क्षेत्रों जैसे अलग-अलग क्षेत्रों के लिए पारवेशी वायु गुणवता और स्तरों के लिए मानक अधिसूचित किए गए हैः विभित्र उपयोगों के लिए लिए जलगुणवता निधार्रित की गई हैः

(2) परिवेशी वायु और जल गुणवत निगरानी केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है;

(3) प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की प्रमुख श्रेणियों में बहिस्त्रावों और उत्सर्जनों के लिए मानक तैयार किए गए हैं। उद्योगों को निधार्रित मानकों का समयबद्ध आधार पर अनुपालन करने के निदेश दिए गए हैं ओर दोषी इकाइयों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती हैं।

(4) प्रमुख विनिर्दिष्ट एवं अन्य गतिविधियों के लिए स्थल चयन से पूर्ण प्रभाव मूल्यांकन के आधार पर पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है।

(5) छोटे पैमाने की औद्योगिकी इकाइयों के समूहों में साझा बहिस्त्राव शोधन संयत्र स्थापति करने की एक स्कीम शुरू की गई है।

(6) उद्योगों के संचालन और स्थल निर्धारण के लिए पर्यावरण दिशा- निर्देश तैयार किए गए हैं।

(7) प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों भीड़-भाड़ वाले इलाकों से अन्यत्र ले जाने के लिए भी वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

(8) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योगों और वाहनों से भित्र स्त्रोतों से होने वाले शोर के नियंत्रण के लिए प्रक्रिया संहिता तैयार की है। इनमें सार्वजनिक संबोधन प्रणाली, वायुमान संचालन, रेल संचालन, निर्माण गतिविधियों और फटाखें फोड़ना शामिल हैं। राज्य सरकारों से संगत स्थानीय अधिनियमों के तहत इन प्रक्रिया संहिताओं का कार्यान्वयन करने को कहा गया है।

(9) मोटर वाहनों नियमावली, 1989 के तहत वाहनो, घरेलु उपकरणों और निर्माण उपस्कारों के लिए शोर की सीमाएं अधिसूचित की गई है।

(10) मोटर वाहन नियमावली 1989 के तहत वाहनों के लिए ठोस व द्रव उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं। भूतल परिवहन मंत्रालय ने राज्य परिवहन निदेशालयों को ठोस उत्सर्जन मानकों को लागू करने की सलाह दी है।

(11) वाहनों से होने वाले उत्सर्जनों के लिए विनिर्माण स्तर पर कड़े मानक अधिसूचित किए गए हैं। जो 1.4..1996 से लागू हो जाएंगे।

(12) बम्बई, कलकत्ता दिल्ली और मद्रास के चार महानगरों में 1.4.1995 से कैटेलिटिक कन्वर्टर लगी कारों मे प्रयोग के लिए सीसा रहित पेट्रोल शुरू किया गया है।

(13) प्रदूषण के प्रभावों पर जनजागरूकता अभियान चलाए गए हैं।

गुजरात में दाहोद स्थित डीजल इंजन और लोको शेड मरम्मत एकक को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव

2311.**श्री गोपाल सिहं जी सोलंकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा यह बताने की कृपा करेगे किः

(क) क्या गुजरात में दाहोद स्थित डीजल इंजन और लोको शेड मरम्मत एकक को अन्यत्र स्थानांतारित करने का प्रस्ताव हैः

(ख) क्या इस प्रस्ताव से रेल कर्मचारी और स्थानीय लोग क्षुब्ध है;

(ग) यदि हां, तो उक्त एकक को दाहोद से स्थानांतरित न होने देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं, और

(घ) देश में ऐसे कितने अन्य डीजल इंजन और लोको शेड मरम्मत एकक कार्यरत हैं और क्या उनमें से कुछ एककों के बन्द होने की संभावना है, यहि हां , तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी नहीं। दाहोद में कोई डीजल रेल इंजन शेड नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारतीय रेलों पर 62 डीजल रेल इंजन शेड हैं। उनमें से किसी भी डीजल रेल इंजन शेड को बंद करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

MEA Officials views on Pakistan

2212. SHRI VIRENDRA KATARIA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to a news item captioned "MEA Officials for tougher line on Pakistan", which appeared in the Times of India, dated 2nd .August, 1995; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and steps proposed to be taken in this regard?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) Government have seen the news item captioned "MEA officials for tougher line of Pakistan" which appeared in the Times of India of 2nd August, 1995.

(b) Government's foreign policy, including, its policy towards Pakistan, is formulated in the overall national interest.

Role of ITI under National Telecom Policy

2213. SHRI S. JAIPAL REDDY: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether the Public Sector ITI Ltd. is now required to produce and supply telecom equipments wanted by the Deptt. of Telecom (DOT) based on lowest quotations by competing with Private Sector on a level playing field;

(b) whether the Private Sectors alongwith foreign companies is now also allowed to enter the basic telecom services while the ITI Ltd. is not being permitted to do so under the National Telecom Policy;

(c) if so, whether Government would revise this decision and agree to allow the ITI Ltd. to enter the basic telecom services; and

(d) what are the plans of Government to provide an effective role to the ITI Ltd. in the light of the National Telecom Policy?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI. P.V. RANGAYYA NAIDU): (a) Yes, Sir. However, with a view to utilise optimally infrastructure of the two PSUs viz. ITI & HTL under Ministry of Communications, the Ministry is following a policy under which 30 to 35% of total DOT orders are kept reserved for ITI & HTL, taken together, for those items which they manufacture. However, this policy is without any compromise in respect of quality, delivery schedule and pricing. The pricing is governed by the process of tendering.

(b) Indian companies registered under the Indian Companies Act, 1956 except the Government Companies have been permitted to bid against the tender floated for the provision of Basic Telecom Services.

(c) It has been decided to preclude the Government Companies including ITI from the basic services as these undertakings have been established by the Government for specific purposes and have sufficient potential for growth in their respective areas. Moreover, Government is keen to ensure a